

VV NEWS

वैशवाश्वारा

साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष: 1 अंक: 2

रविवार 14 फरवरी 2021

देहरादून

मूल्य: 5

पृष्ठ: 8

मुख्यमंत्री रावत ने घोषणाओं की समीक्षा की



देहरादून, संवाददाता। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं चंपावत जिलों की मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की।

बैठक में विधायक बलवंत सिंह भौर्याल, चन्दन राम दास, कैलाश चन्द्र गहतौड़ी, वरुणल माध्यम से विधायक चन्द्रा पंत, विशन सिंह चुफाल उपस्थित थे।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सीएम घोषणाओं को निधिरित समयावधि में पूर्ण किया जाय। स्थानीय

स्तर पर समस्या के त्वरित समाधान के लिए संबंधित विधायकगणों से समन्वय स्थापित किये जाए। हर माह मुख्यमंत्री सीएम घोषणाओं की समीक्षा करेंगे। कार्यों में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारियों को 15 दिनों में घोषणाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिये गये हैं। सीएम घोषणा पोर्टल पर भी सभी घोषणाओं को अपडेट रखने के निर्देश दिये गये।

जनपद पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री की 152 घोषणाओं में से 98 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं।

-आज इन जिलों की समीक्षा

शेष पर कार्य प्रगति पर है। जनपद बागेश्वर में 58 घोषणाओं में से 36 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि शेष पर कार्य चल रहा है। चम्पावत जनपद में 88 घोषणाओं में से 53 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं, अवशेष पर कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि घोषणाओं को समय पर पूर्ण करने के साथ ही कार्यों की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाय। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों पर पेयजल, आवागमन एवं अन्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाय। शौचालयों के निर्माण के साथ ही उनके मॉटेन्स की व्यवस्था भी की जाए। जल के संरक्षण एवं संवर्द्धन की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। पेयजल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं वाले कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।

पिथौरागढ़: पिथौरागढ़ जनपद में मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत मुख्यतः बरम- कनार मोटर मार्ग, सिमल से नाग मोटर मार्ग, डुंगातोली

से चुनगांव मोटर मार्ग, बनकोट से भट्टीगांव मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्यों, अनेक मोटरमार्गों के डामरीकरण सुधारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। डिगरा मुवानी कलौन गाड एवं गुंजी पेयजल योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है। आंवला घाट से पिथौरागढ़ पेयजल योजना पूर्ण की जा चुकी है। डीडोहाट पेयजल योजना एवं मुनस्यारी नगर पेयजल योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है। पिथौरागढ़ को पर्यटक शहर के रूप में विकसित करने के लिए 85.80 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई। पिथौरागढ़ में पार्किंग के निर्माण, मदकोट एवं सेरा स्थित गर्म पानी के झरोतों के विकास, मुनस्यारी को पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने, होम स्टे को बढ़ावा देने एवं हाई टैक शौचालय निर्माण की घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं। थरकोट झील के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। ऐलागाड, तवाघाट एवं धारचुला में तटबंध निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां दी जा

चुकी हैं। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में टेलीरेडियोलॉजी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

बागेश्वर: बागेश्वर जनपद में सीएम घोषणाओं के तहत मुख्यतः पिण्डारी ग्लेशियर ट्रेकिंग रूट के दवाली में 60 मी. स्पान झूला पुल एवं सोराग से सुन्दर ढुंगा तक नये ट्रेकिंग रूट की घोषणा पूर्ण हो चुकी है। बिलौना, कालापैरकापडी, म्यून्डा लिफ्ट सिंचाई योजना, विभिन्न सड़क मार्गों का नव निर्माण एवं डामरीकरण एवं पेयजल योजनाओं से संबंधित घोषणाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है। बागनाथ मंदिर में धर्मशाला एवं बैजनाथ मंदिर गरूड में स्नेहालय निर्माण की घोषणा पूर्ण हो चुकी है।

चम्पावत: चम्पावत जनपद में मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत मुख्यतः जनपद मुख्यालय के सौन्दर्यीकरण, चम्पावत एवं टनकपुर में आधुनिक शौचालयों के निर्माण, जनपद में विभिन्न पार्कों के सौन्दर्यीकरण, वाणासुर एवं चम्पावत में ट्रेकर रूट के विकास, चम्पावत में पार्किंग व बस अड्डा के निर्माण एवं विभिन्न सड़कों के नव निर्माण एवं डामरीकरण के कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

टनल से शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी, 54 पहुंची मृतकों की संख्या

चमोली, संवाददाता। तपोवन में एनटीपीसी के निर्माणाधीन हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल से शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आज भी यहां से तीन शव बरामद किए गए हैं। आपदा के बाद से ही टनल के नीचे एसएफटी (सिल्ट फ्लशिंग टनल) तक पहुंचने में बाधा बन रहे मलबे के विकल्प के तौर पर आजमाया गया ड्रिलिंग का काम रविवार को अंजाम तक तो पहुंचा, लेकिन इसने जिंदगियों को बचाने के लिए पिछले आठ दिनों से चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के हौसले पर प्रहार किए।

एसएफटी के मलबे से पटे होने की जानकारी मिलने से रेस्क्यू टीम, प्रशासन और



टनल में फंसे व्यक्तियों के स्वजनों को निराश कर दिया। अब तक कुल बरामद किए गए कुल 54 शवों और 22 मानव अंगों में से 29 शवों और एक मानव अंग की शिनाख्त की जा चुकी है। जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, उन सभी के डीएनए सैंपल संरक्षित किए

गए हैं। इसके अलावा जोशीमठ थाने में अब तक कुल 179 लोगों की गुमशुदगी दर्ज की जा चुकी है, जबकि अब तक कुल 55 परिजनों के डीएनए सैंपल शिनाख्त में सहायता के लिए लिए गए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है।

तबादला, तीन आईएएस अधिकारियों के तबादले

देहरादून

संवाददाता। उत्तराखंड शासन से आज की बड़ी खबर सामने आ रही है कि 3 आईएएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। आईएएस नितिन



सिंह भदोरिया का तबादला रूप दिया गया है वह जिला अधिकारी अल्मोड़ा के पद पर ही रहेंगे इसके अलावा चंपावत के जिला अधिकारी रहे सुरेंद्र नारायण पांडे को अल्मोड़ा का जिलाधिकारी बनाया गया था उन्हें अब अल्मोड़ा के जिला अधिकारी से पद मुक्त करते हुए सचिव प्रभारी उर्जा उत्तराखंड शासन तथा निदेशक उरेडा के पद पर नई तैनाती मिली है इसके अलावा आर मीनाक्षी सुंदरम को महानिदेशक विद्यालय शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार पूर्वत यथावत कर दिया गया है।

दुखद घटना: सैलाब में बह गया पति, पत्नी बहवास होकर भटक रही

देहरादून, संवाददाता। ऋषि गंगा के सैलाब ने कोलकाता की मधुमिता की दुनिया ही उजाड़ कर रख दी है। तीन महीने पहले ही लालू और मधुमिता की शादी हुई थी। लेकिन अब काल के गाल में समाया लालू मधुमिता को बेसहारा छोड़कर चला गया है। लालू कोलकाता निवासी था और तपोवन परियोजना में मजदूर सप्लायर था। बीते वर्ष नवंबर माह में कोलकाता में शादी करने के बाद पत्नी मधुमिता को भी वह तपोवन ले आया था।

दोनों हंसी-खुशी से रहते थे। ऋषि गंगा में आई बाढ़ के दौरान लालू तपोवन बैराज के समीप

ही था और देखते ही देखते मलबे में बह गया। जब मधुमिता को लालू के बह जाने की सूचना मिली तो वह बहवास होकर गिर पड़ी। जब उसे हेश आया तो रेंती-बिलखती मधुमिता तपोवन बैराज के आसपास लालू को खोजने चली गई।

कुछ स्थानीय लोगों ने उसे ढाँहस बंधाया कि लालू मिल जाएगा, लेकिन एक सप्ताह से मधुमिता और सुरंग साइट अपने पति की खोज में भटक रही है। मधु का देवर व परिजन भी कोलकाता से तपोवन पहुंच गए हैं और उसकी खोज में लगे हैं।

सुरंग में फंसे तपोवन गांव के 24 वर्षीय

अभिषेक की बड़ी बहन पूजा कहती है कि मेरा भाई सुरंग से बचकर आया। सुरंग का मलबा हटाने में देरी नहीं करनी चाहिए और यह कहकर पूजा का गला भर जाता है और वह रोने लगती है। अभिषेक तपोवन परियोजना में इंजीनियर था। आपदा के बाद से उसकी मां पीतांबरी देवी के आंसू नहीं थम रहे हैं वह चारपाई से उठ भी नहीं पा रही है। जबकि पिता ऋषि प्रसाद गुमसुम हैं 7 फरवरी को आई ऋषि गंगा की जल प्रलय को एक सप्ताह का समय हो गया है, लेकिन सुरंग में फंसे लोगों के परिजनों को अभी भी अपनों के सुरक्षित बाहर



आने की उम्मीद है।

मिर्जापुर का जयकिशन परियोजना में फोरमैन के पद पर कार्यरत था। वह भी सुरंग में ही फंसा हुआ है। लापता भाई की खोज में विजय बाबू और साला उदय राज पिछले सात दिनों से जयकिशन के सुरंग से बाहर आने की राह देख रहे हैं। विजय ने बताया कि जयकिशन को अक्टूबर माह से वेतन नहीं मिली थी। वेतन मिलने पर इसी फरवरी में घर आने के लिए कहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस सुरंग में काम कर रहा है, वही सुरंग उसकी जिंदगी को बँद कर देगी।

सम्पादकीय

चीन के चंगुल में न फंसने पाए म्यांमार, अमेरिका को अपनाती होगी दूरदर्शी एवं व्यावहारिक रणनीति

बीते दिनों म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के साथ ही कई सवाल उठने लगे हैं। इनमें एक प्रश्न यह है कि क्या भारत के इस अहम पड़ोसी देश पर पश्चिमी देश प्रतिबंध लगाएंगे और वह फिर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ जाएगा और वहां वैसे हालात बन जाएंगे जैसे लोकतंत्र की शुरुआत से पहले बने हुए थे? 2010 में भारत यात्रा के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने म्यांमार के साथ सक्रिय संवाद वाली भारतीय नीति की आलोचना की थी। हालांकि कुछ महीनों के भीतर खुद ओबामा ने भी वैसी ही नीति अपनाई। फिर 2012 में उनका ऐतिहासिक म्यांमार दौरा हुआ। अब म्यांमार पर प्रतिबंधों का साया फिर से मंडरा रहा है तो क्या इतिहास खुद को दोहराएगा?

भारत की 1,643 किमी लंबी सीमा म्यांमार से लगती है। दोनों देशों के बीच बंगाल की खाड़ी में 725 किमी लंबी तट रेखा भी है। नई दिल्ली म्यांमार को दक्षिणपूर्व एशिया में अपने द्वार के रूप में भी देखती है। भारत अपनी 'एक्ट ईस्ट नीति' के माध्यम से व्यापक आर्थिक एकीकरण में भी लगा है। म्यांमार और भारत के समक्ष कई साझा खतरे भी हैं। इनमें से एक ताकतवर होते बिगड़ते चीन से भी है।

म्यांमार प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। हालांकि आजादी के बाद से ही यहां सेना को छोड़कर कोई अन्य संस्थान फला-फूला नहीं। यहां विभिन्न मतों और नस्ल वाले लोग रहते हैं। उत्तरी एवं पूर्वोत्तर के इलाकों में नस्लीय अलगाववाद की समस्या भी है। हालांकि सेना ने एक दशक पहले देश में चरणबद्ध रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शुरू किया, फिर भी पश्चिमी देशों ने सेना के साथ रिश्ते सहज करने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाए। उन्होंने सिर्फ आंग सान सू की पर ही पूरा दांव लगाया। हालांकि वर्ष 2017 में रोहिंग्या के मसले पर सू की के रवैये से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। रोहिंग्या को म्यांमार से बड़ी तादाद में बेदखल करने के वाक्ये ने 1960 के दशक में म्यांमार से पलायन करने वाले पांच लाख से अधिक भारतीय मूल के लोगों की यादें ताजा करा दी थीं। उस समय म्यांमार सैन्य तानाशाह नेविन की मुट्ठी में था, जिसने 1962 में सत्ता हासिल की। इसके बाद 26 वर्षों तक म्यांमार पूरी दुनिया से कटा रहा। म्यांमार के बर्मीकरण की प्रक्रिया में भारतीयों को वहां से भगाया जा रहा था। नेविन ने भारतीयों को उत्पीड़न का शिकार बनाया। उसने निजी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया। इसका मकसद संपन्न भारतीयों को विपन्न बनाकर वहां से भागने पर विवश करना था। इसके चलते भारत सरकार को भारतीय मूल के लोगों को वहां से लाने के लिए विमान और नौकाएं भेजनी पड़ीं। 1988 तक आते-आते नेविन की विदाई हो गई। तब तक म्यांमार की गिनती दुनिया के दस सबसे गरीब मुल्कों में होने लगी। अनैतिक इतिहास के बावजूद भारत ने अपने हितों को देखते हुए म्यांमार के सैन्य नेतृत्व के साथ सहयोग बढ़ाया। चार महीने पहले ही भारत ने एक किलो क्लास पनडुब्बी की मरम्मत कराकर उसे म्यांमार को उपहारस्वरूप भेंट किया। यह म्यांमार की पहली पनडुब्बी है। भारत ने पिछले महीने ही 15 लाख कोरोना वैक्सीन मुफ्त में म्यांमार को उपलब्ध कराई हैं। गत वर्ष अक्टूबर में भारतीय सेना प्रमुख और विदेश सचिव ने म्यांमार का दौरा किया था। यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। ध्यान रहे कि चीन उत्तरी म्यांमार में विद्रोही समूहों को मदद पहुंचाता है। ये विद्रोही भारत के खिलाफ भी मोर्चा खोल सकते हैं। असल में वे भारत-म्यांमार सीमा के दोनों ओर सक्रिय हैं। इसे देखते हुए भारत को म्यांमार की सेना के सहयोग की दरकार है। बीते दिनों हुए सैन्य तख्तापलट ने म्यांमार को लेकर अमेरिकी नीति की एक बड़ी खामी को उजागर कर दिया। वह सैन्य नेतृत्व के साथ कोई कड़ी नहीं जोड़ सका। वास्तव में अमेरिका नवंबर 2019 तक म्यांमार के शीर्ष सैन्य नेतृत्व पर शिकंजा कसे रहा। रौहंग्या मुसलमानों के दमन को नस्लीय सफाया करार देकर उसने दिसंबर 2017 से जनरलों पर वीजा प्रतिबंध लगाए रखने के साथ ही देश पर आर्थिक प्रतिबंध भी जारी रखे। अमेरिका इस सच्चाई को समझने में नाकाम रहा कि म्यांमार में लोकतंत्र को कायम रखने में सेना का सहयोग आवश्यक होगा, अन्यथा वहां सैन्य शासन वापस लौट आएगा। लोकतंत्र को सैन्य नेतृत्व के निरंतर समर्थन के एवज में उसे प्रोत्साहन देने के बजाय अमेरिका उलट व्यवहार ही करता रहा। म्यांमार को लेकर गलत अमेरिकी आकलन ने नए सैन्य शासन के साथ वाशिंगटन के लिए बहुत कम गुंजाइश छोड़ी है। अमेरिका अगर फिर से 2012 से पहले वाले प्रतिबंधों के उस दौर में वापस लौटता है जब 25 वर्षों की पश्चिमी सख्ती के कारण म्यांमार को बड़ी हिचक के साथ चीन की गोद में जाकर बैठना पड़ा था तो यह अमेरिका का सबसे खराब दांव होगा। ऐसी कोई भी नीति म्यांमार को लेकर अमेरिका की नाकामी को और उलझाएगी। अमेरिका के नेतृत्व में म्यांमार को अलग-थलग करने की कोशिश चीनी तानाशाह शी चिनफंग को उस देश में आक्रामक रूप से अपने हितों को पोषित करने का अवसर प्रदान करेगी।

म्यांमार की अति-राष्ट्रवादी सेना चीन पर भरोसा नहीं करती। उसका मानना है कि म्यांमार की सेना और सरकार को साधने के लिए ही चीन वहां अलगाववाद को मदद करता है। म्यांमार के जनरलों को असल में चीन के साथ सू की की बढ़ती नजदीकी भी खटक रही थी। यह नजदीकी तब दिखी भी जब 13 महीने पहले शी ने म्यांमार दौरे के दौरान 33 द्विपक्षीय संबंधों पर हस्ताक्षर किए। यह दो दशकों में किसी चीनी नेता का पहला म्यांमार दौरा था। जनरलों ने चीन पर म्यांमार की निर्भरता घटाने के लिए ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू की थी, ताकि वे लोकतांत्रिक देशों के साथ संबंध बढ़ाकर अपनी विदेश नीति को संतुलन दे सकें। ऐसे में यह उनके लिए अंतिम विकल्प होगा कि उनका देश फिर से चीन के साये में चला जाए। ऐसे परिदृश्य में भारत को अमेरिका को इसके लिए समझाना चाहिए कि म्यांमार को लेकर प्रतिबंधों के बजाय प्रोत्साहन आधारित दूरदर्शी एवं व्यावहारिक रणनीति अपनाने की दरकार है। अमेरिकियों को भारत और जापान जैसे अपने उन मित्र देशों के साथ अवश्य परामर्श करना चाहिए, जिन्होंने म्यांमार में भारी निवेश किया है और उसके सैन्य नेतृत्व से बढ़िया रिश्ते बनाए हैं। भारत और जापान की नीतियों की धुरी रणनीतिक रूप से इस अहम देश में चीनी प्रभाव की काट करने पर टिकी हुई है।



फ्रांस ने दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के बढ़ते प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए अपनी एक परमाणु पनडुब्बी तैनात की है। इससे दक्षिण चीन सागर में संघर्ष की आशंका तेज हो गई है। ऐसे में सवाल है कि अब दक्षिण चीन सागर में उसकी नई रणनीति क्या होगी।

चीन ने बीबीसी पर लगाया प्रतिबंध, कोरोना और शिनजियांग पर गलत रिपोर्टिंग का लगाया आरोप



बीजिंग, एजेंसी। चीन और पश्चिमी देशों के बीच तनातनी बनी हुई है। इसी कड़ी चीन ने ब्रिटिश टेलीविजन चैनल बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन के राष्ट्रीय रेडियो और टेलीविजन प्रशासन (एनआरटीए) ने गुरुवार को प्रतिबंध की घोषणा करते हुए कहा कि बीबीसी ने कोविड-19 और शिनजियांग को लेकर गलत रिपोर्टिंग की है। डूंगन ने यह भी कहा कि बीबीसी ने न्यूज के सत्य और निष्पक्ष होने की आवश्यक शर्त का भी उल्लंघन किया है।

एनआरटीए ने आरोप लगाया कि बीबीसी द्वारा प्रसारित की गई रिपोर्टों से

चीन के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा है और उसकी राष्ट्रीय एकता भी कमजोर हुई है। बीबीसी चीन में प्रसारण करने वाले विदेशी चैनलों के आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता है। ऐसे में चीन ने बीबीसी पर अगले साल तक प्रसारण के लिए आवेदन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले 4 फरवरी को ब्रिटेन ने चीन के सरकारी मीडिया सीजीटीएन को अपने देश में प्रतिबंधित किया था, उसके बाद से इस बात की चर्चा थी कि चीन भी इसके प्रत्युत्तर में बीबीसी को प्रतिबंधित करेगा। प्रतिबंध के दौरान ब्रिटेन की जांच में पाया गया था कि सीजीटीएन के पास

संपादकीय नियंत्रण का अभाव था। इसके अलावा इस चैनल का संबंध चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी था।

ब्रिटिश विदेश मंत्री डॉमिनिक रैब ने गुरुवार को बीबीसी वर्ल्ड न्यूज चैनल पर प्रतिबंध लगाने के चीन के फैसले को अस्वीकार्य बताया और कहा कि इससे चीन के वैश्विक रुख को नुकसान पहुंचा है। रैब ने ट्विटर पर कहा कि चीन में बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय चीन की मीडिया स्वतंत्रता की अस्वीकार्यता है। चीन ने दुनिया भर में मीडिया और इंटरनेट की स्वतंत्रता पर कुछ सबसे गंभीर प्रतिबंध लगाए हैं और यह ताजा कदम दुनिया की नजर में चीन की प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा।

ब्रिटेन के बीबीसी प्रसारणकर्ता ने गुरुवार को प्रतिबंध लगाए जाने पर निराशा व्यक्त की है। बीबीसी के प्रवक्ता ने एक ईमेल में दिए बयान में कहा कि चीन अधिकारियों की इस कार्रवाई से हम निराश हैं। बीबीसी दुनिया का सबसे भरोसेमंद अंतरराष्ट्रीय समाचार प्रसारक है और दुनिया भर की स्टोरी को निष्पक्ष और बिना किसी डर या पक्ष के रिपोर्ट करता है।

दक्षिण चीन सागर में अमेरिका को मिला फ्रांस का साथ, तैनात की परमाणु पनडुब्बी

हांगकांग/वाशिंगटन, एजेंसी। फ्रांस ने दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के बढ़ते प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए अपनी एक परमाणु पनडुब्बी को तैनात किया है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा था कि दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा चरम पर पहुंच चुकी है। बाइडन ने इसके साथ यूरोप और एशिया में समान विचारधारा वाले सहयोगी देशों का आह्वान किया था। फ्रांस के इस कदम को बाइडन के इस आह्वान से जोड़कर देखा जा रहा है। फ्रांस के इस कदम से दक्षिण चीन सागर में संघर्ष की आशंका तेज हो गई है। बाइडन की इस अपील का असर यूरोपीय देशों पर पड़ा है। ऐसे में सवाल यह है कि अब दक्षिण चीन सागर में चीन की नई रणनीति क्या होगी।

फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पारली ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि पेरिस का यह कदम अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुरूप है और यह फ्रांसीसी नौसेना की क्षमता का भी प्रमाण है। उन्होंने कहा कि हमारी नौसेना लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के रणनीतिक साझेदार हैं।

आर्मेनिया ने उठाई पाकिस्तान को एफएटीएफ की काली सूची में डाले जाने की मांग

काबुल, एजेंसी। पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाला देश है। इसकी पुष्टि पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारे अलकायदा आतंकी उमर सईद शेख को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी किए जाने से होती है। अफगानिस्तान टाइम्स में गफूर अहमद द्वारा लिखे गए लेख में फ्रेंसले को न्याय का कुरू मजाक बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि इससे यह संकेत मिलता है कि पाक सेना आतंकियों की सुरक्षा के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है। उधर, अमेरिका स्थित आर्मेनियाई समुदाय ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) से इस्लामाबाद को काली सूची में डालने की मांग की है। बता दें कि आर्मेनिया लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि उसके खिलाफ लड़ने के लिए इस्लामाबाद जेहादी आतंकियों को मनी लाँडिंग के माध्यम से फंड उपलब्ध कराता है। गफूर ने कहा कि शेख पाकिस्तानी अदालतों द्वारा रिहा किया जाने वाला पहला आतंकवादी नहीं है। लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख और वैश्विक आतंकी हाफिज सईद को कई बार सुबूतों के अभाव में रिहा किया जा चुका है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि सेना के पक्ष में शीर्ष न्यायपालिका किस तरह से लंबे समय से काम कर रही है। शेख के बरी होने से पता चलता है कि सेना अपने लोगों की रक्षा के लिए किस हद तक जा सकती है। सईद को रिहा किए जाने से पाकिस्तान के उन कदमों पर भी प्रश्नचिह्न लग गया है जो उसने एफएटीएफ शर्तों को पूरा करने के लिए उठाया है। इसमें टेरर फंडिंग के मामले में हाफिज सईद और दूसरे आतंकियों को सजा सुनाया जाना शामिल है। बता दें कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। एफएटीएफ की अगली बैठक फरवरी में होगी है। अगर पाकिस्तान को इस सूची से बाहर निकलना है तो उसे टेरर फंडिंग के खिलाफ कई कदम उठाने होंगे। वर्ष 2002 में कराची में द वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख पर्ल (38) का उस समय अपहरण कर लिया गया था, जब वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ और अलकायदा के बीच संबंधों पर एक खबर के लिए जानकारी जुटा रहे थे। इसके बाद सिर कलम करके उनकी हत्या कर दी गई थी।

राहुल के आरोप पर भाजपा का पलटवार, कांग्रेस काल में चीन ने 43 हजार हेक्टेयर भूमि पर किया था कब्जा: नड्डा



नई दिल्ली, एजेंसी। यू. तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि लद्दाख में शुरू हुई भारत व चीन के सैनिकों की वापसी प्रक्रिया में भारत ने एक इंच भी जमीन नहीं खोई है लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं दिख रहे। यही कारण है कि कांग्रेस-भाजपा में इस मसले को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई। शुक्रवार को एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार ने चीन को भारत की जमीन पर कब्जा करने की छूट दे दी। राहुल के बेटुके आरोपों पर तीखा पलटवार करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया को सेना देख रही है। राहुल ने उसका अपमान किया है।

पूर्व सैनिकों के कुछ वीडियो को टैग करते हुए नड्डा ने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस काल में ही चीन ने 43 हजार हेक्टेयर भारतीय

कोरोना के इलाज में एड ऑन मेडिसिन के रूप में होम्योपैथिक दवाइयां भी होंगी शामिल

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री किरन रिजजू ने शुक्रवार को सदन में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के उपचार में मानक देखभाल के लिए एड-ऑन के रूप में होम्योपैथी दवाओं के उपयोग की अनुमति देने के लिए आयुष मंत्रालय की सलाह को बर्करार रखा है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में युवा मामलों और खेल मंत्री व आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार रखने वाले किरन रिजजू ने बताया कि अंग्रेजी दवाओं और होम्योपैथी सहित मानक देखभाल में एड-ऑन की अनुमति मिली है। उन्होंने बताया कि आयुष मंत्रालय ने कोरोना से संबंधित उपचार के लिए होम्योपैथी सहित चिकित्सा की अन्य प्रणालियों की मदद से कई कदम उठाए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने 6 मार्च 2020 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्रालय के पत्र का हवाला दिया। जिसमें लोगों की सामान्य प्रतिरक्षा और संभावित आयुष हस्तक्षेपों के बारे में विशिष्ट सुझाव दिए गए थे। उन्होंने 31 मार्च 2020 को स्वास्थ्य संबंधी निवारक उपायों और ध्वसन स्वास्थ्य के लिए विशेष संदर्भ के साथ प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए जारी किए गए स्व-देखभाल दिशानिर्देशों का भी उल्लेख किया।

भीमा हत्याकांड के मोस्ट वांटेड की एनआइए ने जारी की लिस्ट

दंतेवाड़ा, एजेंसी। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड में एनआइए ने शुक्रवार को 22 मोस्ट वांटेड नक्सलियों की सूची जारी कर दी है। इधर बैलाडीला की तराई में डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) के जवान और नक्सलियों के बीच शुक्रवार को मुठभेड़ हो गई। इसमें एक नक्सली के मारे जाने और अन्य को गोली लगने की सूचना है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआइए) की 22 मोस्ट वांटेड नक्सलियों सूची को अंचल के ग्रामीण इलाकों में चरपा किया जाएगा। सूची में शामिल नक्सलियों पर 20 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक का इनाम भी घोषित किया है। याद रहे लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दंतेवाड़ा

भूमि पर कब्जा किया था। सैनिकों को बहादुरी से लड़ने से रोका था और अब सेना पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं राहुल ने कहा कि पैगोंग झील के इलाके में फिंगर चार के बजाय भारतीय सैनिकों के फिंगर तीन तक सीमित रहने से साफ है कि सैनिकों की वापसी के इस समझौते में भारत ने कैलास रेंज में अपने बहादुर सैनिकों के हाथ आई रणनीतिक बढ़त को गंवाया है।

राहुल ने कहा कि एलएसी के मौजूदा गतिरोध को लेकर सरकार का रुख यह था कि अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल करनी है। सरकार इसी पर बात कर रही थी। लेकिन राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, उससे साफ है कि यथास्थिति को सरकार भूल गई और चीन के सामने झुक गई। इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को देना होगा कि भारतीय भू-भाग चीन को क्यों सौंपा गया? राहुल ने सवाल किया कि

पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 11 की मौत और 36 घायल, केंद्र और राज्य सरकार ने किया मुआवजे का एलान

चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु के दक्षिणी जिले में सत्तूर के निकट पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से कम-से-कम 11 मजदूरों की मौत हो गई और 36 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि अचानकूलम गांव में स्थित फैक्ट्री में यह विस्फोट उस समय हुआ जब पटाखा बनाने के लिए कुछ रसायनों को मिलाया जा रहा था। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हादसे पर दुख जताया है। मोदी ने मृतकों के स्वजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से दो-दो लाख की मदद का एलान किया है। पलानीस्वामी ने भी मृतकों के स्वजनों को मुख्यमंत्री जन राहत कोष से तीन लाख रुपये की मदद देने की घोषणा की है। पलानीस्वामी ने घटना की जांच का आदेश देते हुए आश्वासन दिया कि मामले में उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विस्फोट के चलते फैक्ट्री की इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है।

प्रधानमंत्री ने कहा- तमिलनाडु के विरुधुनगर में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में लगी आग की घटना दुःख है। दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो भी घायल हुए हैं वे जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इस घटना से प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए प्रशासन काम कर रहा है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हादसे को लेकर दुख जताया है। उन्होंने राज्य सरकार से पीड़ितों की मदद की अपील की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा पीड़ितों के परिवार के प्रति दिल से सांत्वना व्यक्त करता हूँ। जो लोग अभी भी फैक्ट्री के अंदर फंसे हुए हैं उसके बारे में सोचना हृदय विदारक है। मैं राज्य सरकार से यह अपील करता हूँ कि तुरंत बचाव, मदद और राहत मुहैया कराएं।

के श्यामगिरी में नक्सलियों ने बारूदी विस्फोट कर तत्कालीन विधायक भीमा मंडावी का वाहन उड़ा दिया था। इसमें विधायक सहित चार जवान शहीद हो गए थे। मामले की जांच पुलिस के बाद एनआइए कर रही है।

एसपी डा. अभिषेक पल्लव के मुताबिक, अब तक भीमा मंडावी हत्याकांड में जुड़े चार नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर एनआइए को सौंपा है। तीन नक्सली मुठभेड़ में मारे गए और तीन ने आत्मसमर्पण किया है। सूची में जिन 22 नक्सलियों का जिक्र है, वो ज्यादातर दरभा डिवीजन कमेटी के सदस्य हैं। इसके अलावा तेलंगाना, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में सक्रिय नक्सली हैं, जो मालांगिर, कटेकल्याण व कांगिराटी एरिया कमेटी से जुड़े हैं।

रणनीतिक लिहाज से अहम इलाकों डेपसांग, गोगरा और हॉट स्पिंग से चीनी पीछे क्यों नहीं हटे हैं? ऐसे में हमारे सैनिकों को कैलास रेंज से पीछे हटाने से भारत को क्या हसिल हुआ है? कांग्रेस नेता ने यह आरोप भी लगाया कि चीन को अपनी जमीन सौंपने की बात कहने से बचने के लिए प्रधानमंत्री ने खुद के बजाय रक्षा मंत्री से संसद में बयान दिलाया।

भाजपा की ओर से जवाबी हमला बहुत तेज था। नड्डा ने कहा कि यह आश्चर्य नहीं कि पूरी स्थिति स्पष्ट किए जाने के बावजूद राहुल गांधी की ओर से सेना पर सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है? दरअसल कांग्रेस ने कभी भी सेना पर भरोसा नहीं किया और सेना को भी कांग्रेस नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा।

नड्डा ने कुछ पूर्व सैनिक अधिकारियों के बयान और वीडियो भी ट्वीट किए, जिसमें उनकी ओर से आरोप लगाया गया था कि संप्रग काल में वे पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहते थे। लेकिन महीनों इंतजार के बावजूद मंजूरी नहीं मिली। नड्डा ने रिटायर्ड एयर मार्शल प्रणब कुमार बारबोरा का एक साक्षात्कार भी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि 2008 में उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व और तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी से मंजूरी लिए बौर ही लद्दाख में दौलतबेग ओल्डी को फिर से एक्टिव किया था, क्योंकि वह जानते थे मंजूरी नहीं मिलेगी। इससे पहले चार बार भी कुछ अधिकारियों ने मंजूरी मांगी थी जो फाइलों में दब गई थी।

संक्षिप्त समाचार

देश में तेजी से हो रहा कोरोना का टीकाकरण, अब तक 77 लाख से ज्यादा लोगों को दी गई वैक्सीन



नई दिल्ली, एजेंसी। देश में तेजी के साथ कोरोना का टीकाकरण किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 12 फरवरी शाम 6 बजे तक कुल 77,66,319 लोगों को कोरोना का टीकाकरण किया गया है। इनमें से 58,65,813 हेल्थकेयर वर्कों का टीकाकरण शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि कम से कम एक बार कोरोना का टीकाकरण के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए शेड्यूल 20 फरवरी तक किया जाना है। स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए कोरोना का टीकाकरण का रण्ड अप 25 फरवरी तक समाप्त हो जाएगा। वहीं, फ्रंटलाइन वर्कों (पुलिस व अन्य प्रशासन के अधिकारियों) के टीकाकरण की शेड्यूलिंग 1 मार्च के लिए तय की गई है। जिन्हें किसी भी कारण से टीका नहीं लगाया जा सकता है, उनके लिए रण्ड अप 6 मार्च तक रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना का टीकाकरण के दौरान 33 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसमें से 21 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। दो का अभी इलाज चल रहा है और दस लोगों की मौत हो चुकी है। देशभर में कोरोना का टीकाकरण के बीच अस्पताल में भर्ती का फीसद 0.0004 है। इसके साथ ही मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में अस्पताल में भर्ती होने की नई घटना एनाफिलेक्सिस का मामला है, जिसका इलाज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में किया गया और अब उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई।

केंद्र सरकार की कड़ी फटकार के बाद ट्विटर ने आपत्ति वाले 97 फीसद अकाउंट किए ब्लॉक

नई दिल्ली, एजेंसी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनों के बारे में दुष्प्रचार और भड़काऊ सामग्री वाले अकाउंट्स पर सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय की आपत्ति के बाद ट्विटर ने ऐसे करीब 97 फीसद अकाउंट्स और पोस्ट ब्लॉक कर दिए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी सचिव और ट्विटर के प्रतिनिधियों के बीच बुधवार शाम को हुई बैठक के बाद यह कदम उठाया गया है। इस बैठक में अमेरिकी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को स्थानीय कानूनों का पालन करने या कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने की कड़ी चेतावनी दी गई थी। मंत्रालय ने कानून-व्यवस्था पर असर डाल सकने वाली भड़काऊ सामग्री को ब्लॉक करने के उसके आदेश पर कार्रवाई में ट्विटर की ओर से विलंब पर सवाल उठाया था, जबकि अमेरिकी कंपनी ने अमेरिका में कैपिटल हिल पर हुई इसी तरह की घटना पर तत्काल कदम उठाया था। सूत्रों के मुताबिक, ट्विटर ने अब आदेशों का पालन किया है और सरकार की ओर से आपत्ति वाले 97 फीसद से अधिक अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। हालांकि इस मामले में ट्विटर ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। चार फरवरी को ट्विटर से पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थकों से जुड़े 1,178 अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था। इन अकाउंट्स से कृषि कानून विरोधी आंदोलन के बारे में दुष्प्रचार और भड़काऊ सामग्री का प्रसार किया जा रहा था।

कृषि सुधार कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की समिति ने आठ राज्यों की 12 किसान यूनियनों से किया विचार-विमर्श

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त की समिति ने केंद्र सरकार के लिए विवादित कृषि सुधार कानूनों पर आठ राज्यों की 12 किसान यूनियनों से विचार-विमर्श किया है। शुक्रवार को इस सिलसिले में यह सातवाँ बैठक हुई है। तीन सदस्यीय समिति सभी पक्षकारों से आमने-सामने की बैठक और ऑनलाइन वार्ता के जरिये विचार-विमर्श कर रही है। समिति ने एक बयान जारी करके कहा कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये किसानों, किसान यूनियनों और कृषि उत्पाद संगठनों से बातचीत की है। समिति के सदस्यों के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के किसानों और किसान यूनियनों से तीनों कृषि सुधार कानूनों पर कई दिनों तक गहन चर्चा हुई है। उल्लेखनीय है कि विगत 12 जनवरी को सर्वोच्च अदालत ने इन तीनों कृषि कानूनों के अमल पर दो महीने के लिए रोक लगा दी थी। साथ ही समिति से सभी पक्षों से विचार-विमर्श के बाद दो माह में अपनी रिपोर्ट देने को कहा था।

जिस भारत भवन के निर्माण में ईट-पत्थर ढोए, पद्मश्री पाकर वहीं मुख्य अतिथि बनेंगी भूरीबाई

भोपाल, एजेंसी। यदि किसी के पास योग्यता हो और उसे प्रोत्साहित करने वाले मिल जाएं तो आम व्यक्ति भी शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित हुई चित्रकार भूरीबाई इसका उदाहरण हैं। दरअसल, बहुकला केंद्र के रूप में प्रसिद्ध भोपाल स्थित भारत भवन के निर्माण के दौरान उन्होंने मजदूर के रूप में यहां ईट-पत्थर ढोए थे। उन्हें छह रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलती थी। अब भूरीबाई प्रख्यात चित्रकार के रूप में स्थापना दिवस समारोह की मुख्य अतिथि होंगी। मशहूर कलाधर्मी और भारत भवन के पहले प्रमुख रहे जे. स्वामीनाथन ने उनकी कला को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ाया। इस मायने में 13 फरवरी को भारत भवन का 39वां स्थापना दिवस बेहद खास रहने वाला है। भूरीबाई ने बताया कि 40 साल पहले भारत भवन से जुड़ना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। उन दिनों मुझे यह पता नहीं था कि यहां कोई कला केंद्र आकार लेने वाला है। मैं तो सिर्फ एक इमारत में काम करने आई थीं। यहां ईट-पत्थर ढोकर घर चलाना मेरा उद्देश्य था। यह बात अलग है कि काम करते-करते मैं यहां से जुड़ गई। जे. स्वामीनाथन ने मेरी प्रतिभा को पहचाना, मुझे मौका दिया, मेरी कला को निखारा और मंच उपलब्ध कराया। मुख्य अतिथि के रूप में इसके वर्षगांठ समारोह में शामिल होना मेरे लिए भावुक कर देने वाला क्षण होगा।

टोल पर भुगतान के लिए गाड़ियों में फास्टैग जरूरी - नहीं तो लगेगा दो गुना शुल्क



नई दिल्ली, संवाददाता। पूरे देश में आज से नेशनल हाइवे टोल पर भुगतान के लिए फास्ट टैग अनिवार्य हो गया है। जिस गाड़ी पर फास्ट टैग नहीं होगा, उसपर भारी जुर्माना जुर्माना लगेगा। हालांकि टू व्हीलर वाहनों को फास्टैग से छूट दी गई है। आपको बता दें कि फास्टैग साल 2011 में लागू किया गया

था। इसके बाद साल 2017 के बाद खरीदे जाने वाले सभी वाहनों के लिए फास्टैग को जरूरी कर दिया गया था।

सरकार की तैयारी है कि 15 फरवरी

से 100 फीसदी टोल फास्टैग की मदद से ही कलेक्ट किया जा सके। फिलहाल नेशनल हाइवे से जितने भी टोल टैक्स आते हैं, उनमें 80 फीसद ही फास्ट टैग से आते हैं। अब अगर गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा होगा तो चालक को टोल प्लाजा पार करने के लिए दोगुना टोल टैक्स या जुर्माना देना होगा।

जानिए क्या होता है फास्टैग

फास्टैग एक प्रकार का टैग या स्टिकर होता है। यह वाहन की विंडस्क्रीन पर लगा हुआ होता है। फास्टैग रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या थ्रू तकनीक पर काम करता है। इस तकनीक के जरिए

टोल प्लाजा पर लगे कैमरे स्टिकर के बार-कोड को स्कैन कर लेते हैं और टोल फीस अपने आप फास्टैग के वॉलेट से कट जाती है।

आपको बता दें कि नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से परिवहन विभाग को पत्र भेजा गया है। इसके तहत 15 फरवरी की रात 12 बजे से रोडवेज की बसों में भी फास्टैग अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में वह बसें भी दोगुने शुल्क की वसूली के दायरे में आ जाएंगी। वहीं, परिवहन निगम के जीएम संचालन दीपक जैन का कहना है कि सभी बसों में पहले से ही फास्टैग लगा दिए गए हैं।

चार घंटे खुलेंगे हाउस टैक्स काउंटर

देहरादून संवाददाता। मह के द्वितीय शनिवार के चलते अवकाश होने के बावजूद आज शहरवासी नगर निगम जाकर हाउस टैक्स जमा करा सकते हैं। निगम की ओर से टैक्स में दी जा रही छूट के अब दो दिन शेष रहने और टैक्स वसूली में बढ़ोत्तरी के लिए नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने शनिवार को चार घंटे हाउस टैक्स अनुभाग खोलने के आदेश दिए हैं। सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक हाउस टैक्स काउंटर खुले रहेंगे।



कोरोना काल के कारण नगर निगम इस वित्तीय वर्ष में हाउस टैक्स वसूली में काफी पीछे चल रहा है। दरअसल, लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष के शुरुआती तीन महीने शहरवासी टैक्स जमा नहीं करा पाए जबकि इसके बाद कोरोना के बढ़ते प्रसार ने घर से बाहर निकलने में आमजन के कदम थामे रखे। पिछले साल निगम जनवरी तक तीस करोड़ रुपये की वसूली पार कर चुका था, जो इस वर्ष फरवरी मध्य तक लगभग 22 करोड़ तक ही पहुंची है। नगर निगम समय से टैक्स जमा कराने वालों को हर साल 20 फीसद की छूट देता है।

इस साल इस छूट के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया। अब यह छूट पाने के लिए दो ही दिन शेष हैं। उसमें भी शनिवार को चार घंटे मिलेंगे, जबकि सोमवार को सात घंटे। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि आमजन को राहत देने के लिए शनिवार को टैक्स काउंटर चार घंटे खोले रखने का आदेश दिया गया है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि छूट की सीमा आगे नहीं बढ़ेगी।

मौत को मात देने वाले की आपबीती

चमोली, संवाददाता। चमोली जिले के रैणी गांव में 7 फरवरी रविवार के दिन आई आपदा के बाद लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। आपदा की चपेट में आए कई लोगों को हमारे सुरक्षाकर्मियों द्वारा रेस्क्यू कर बचाया गया। चमोली आपदा की चपेट में आए और मौत को मात देकर वापस लौटे एक शख्स ने अपनी आपबीती मीडिया को सुनाई और बताया कि कैसे हमेशा से प्रकृति के खिलाफ काम करने पर भी प्रकृति ने उसे बचाया।

जी हां बता दें कि इस आपदा में मौत को मात देकर लौटे लम्बागढ़ गांव निवासी 49 साल के विक्रम चौहान ने बताया कि आपदा वाले दिन यानी की रविवार वो रोज की तरह सुबह काम पर गए थे। अचानक ठंडे पानी का सैलाब आया और हम सबको अपने साथ ले गया। आपबीती सुनाते हुए कहा कि वो एक पेड़ से टकराए जिसे उन्होंने पूरी ताकत से पकड़ लिया और अगले 30 मिनट तक वैसी लटक रहे।

उन्होंने बताया कि रैणी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें देखा और मदद के दौड़े आए। उन्हें वहां से बाहर निकाला। विक्रम सिंह ने बताया कि ठंडे पानी में भीगने के कारण वो ठिठुर रहे



थे। रैणी गांव के लोगों ने मुझे रेस्क्यू कर तुरंत पास में मौजूद एक गर्म जलधारे में स्त्रोत में डुबाया। विक्रम ने रोते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा पहाड़ों को काटा और जमीन खोदी जो की उनका काम था। कहा कि उन्होंने कभी प्रकृति की चिंता नहीं की लेकिन आज उसी प्रकृति ने उसे बचाया है। विक्रम चौहान ने मीडिया को बताया कि 7 फरवरी के दिन वो डैम पर ही मौजूद थे। उन्होंने मौत का पूरा मंजर अपनी आँखों से देखा। विक्रम सिंह का कहना है कि मैं पेड़ों को सम्मान देता था क्योंकि वो हमें जीने के लिये ऑक्सीजन देते हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर उस दिन मैंने जिन्दगी का एक महत्वपूर्ण सबक

अब मात्र दो घन्टे पहुँच जाएंगे दिल्ली से देहरादून

देहरादून, संवाददाता। दिल्ली देहरादून जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। जहाँ पहले दिल्ली से देहरादून आने के लिए जाम का सामना करना पड़ता था और कई घंटे दिल्ली से देहरादून आने में लग जाते थे वहीं अब दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली जाने में काफी कम समय लगेगा।

अब दिल्ली से देहरादून की दूरी 6 घंटे के बजाय 2 घंटे रह जाएगी। दिल्ली से देहरादून के बीच 210 किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। ये देश का पहला हाईवे होगा जहाँ वन्य जीवों को रास्ता देने के लिए 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये कॉरिडोर वन्य जीवों को सुरक्षित रास्ता उपलब्ध करवाएगा और आम आवाजाही भी सुगम बनी रहेगी।

अक्षरधाम से देहरादून की लंबाई 210 कि लिए 4 खंडों में विभाजित किया गया है।

पहला फेज- अक्षरधाम से EPE जंक्शन 31 किमी, इसे 6 लेन में विकसित किया जा रहा, ये हिस्सा अक्षरधाम मंदिर से शुरू होगा और गीता कॉलोनी, खजूरी खास, मंडोला, आदि से होकर गुजरेगा।

दूसरा फेज- ईपीई जंक्शन से सहारनपुर

बाईपास 118 किमी, ये हिस्सा भी 6 लेन का बनाया जा रहा है और पूरी लंबाई बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिलों से गुजर रही है। तीसरा फेज- सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर 41 किलोमीटर, ये हिस्सा सहारनपुर बाईपास से शुरू होती है और गणेशपुर पर समाप्त होती है। न्यूनतम 100 किमी प्रति घंटे की गति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अंडरपास और सर्विस रोड की योजना बनाई जा रही है।

चौथा फेज- गणेशपुर से देहरादून 20 किमी लम्बाई है, ये हिस्सा 6 लेन का होगा। यह खंड मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में आरक्षित वन से होकर गुजरता है। 20 किमी में से, 5 किमी का विस्तार ब्राउनफील्ड है, और 15 किमी की ऊंचाई वन्य जीवन कॉरिडोर तकरीबन 12 किमी और इसमें वन्य जीवों के लिए सुगम मार्ग उपलब्ध कराने के लिए एक सुरंग जो



340 मीटर लम्बी होगी का भी निर्माण होगा।

इस योजना के लिए जरूरी फॉरस्ट एंड वाइल्डलाइफ क्लियरेंस मिल चुका है। प्रोजेक्ट की कुल पूंजी लागत 12300 करोड़ है पूरे कॉरिडोर को न्यूनतम 100 किमी

प्रति घंटे की गति के लिए डिजाइन किया गया है। हाईवे बनने के बाद यात्रा का समय 2 घंटा रह जाएगा। वर्तमान में 6 घंटा समय लगता है। वर्तमान में दूरी 235 किमी है जो घटकर 210 किमी रह जाएगी।

ऊधमसिंह नगर में खुलेगा बाल मित्र थाना, वर्दी में नहीं रहेंगे पुलिसकर्मी

ऊधमसिंह संवाददाता

ऊधमसिंह नगर। कानून के दायरे में फसे बच्चों को भी अब बेहतर माहौल मिल सकेगा। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस विशेष प्रयास कर रही है। ऊधमसिंह नगर के काशीपुर या रुद्रपुर कोतवाली में से किसी एक स्थान पर जल्द बाल मित्र थाना खोला जाएगा। ताकि बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ ही बच्चों को भयमुक्त वातावरण दिया जा सके। महकमे ने इस बाबत तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया के तहत कई मामलों में कानून के दायरे में बच्चे भी फंस जाते हैं। इनमें वारदात में शामिल बच्चों के साथ ही लावारिस या गुमशुदा बच्चे होते हैं। ऐसे में उन्हें भी कोतवाली या फिर चौकी में रखना पुलिस की मजबूरी हो जाती है। इसके कारण उनकी मनोदशा पर बुरा असर पड़ता है। इसे देखते हुए राज्य के सभी जिलों में बाल मित्र थाने खोले जाने की कवायद शुरू हुई है। देहरादून के डालनवाला में ऐसा थाना खुल चुका है। अब ऊधमसिंह नगर में भी पुलिस महकमे ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। काशीपुर व रुद्रपुर में से किसी एक स्थान पर निर्णय होना बाकी है। निर्णय होते ही कुछ सप्ताह में बाल मित्र थाना खुल जाएगा। एसपी सिटी ममता बोहरा ने बताया कि देहरादून के डालनवाला थाने में बाल मित्र थाना खोला गया है। अब राज्य के अन्य जिलों में भी बाल मित्र थाने खोले जा रहे हैं। इसके लिए रुद्रपुर व काशीपुर में से किसी एक कोतवाली में चयन किया जाना है। इस बाबत निर्णय जल्द लिया जाएगा। वर्दी में नहीं रहेंगे पुलिसकर्मी बाल मित्र थाने में उप निरीक्षक रैंक के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे। इसके अलावा पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगेगी, जो वर्दी में नहीं रहेंगे। जरूरत पड़ने पर आयोग, वन स्टॉप सेंटर और अस्पतालों के काउंसलर बच्चों की काउंसलिंग भी करेंगे। बाल मित्र थाने की मानीटरिंग सीओ स्तर पर होगी। मिलेंगी रोचक जानकारी बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें कविताएं, कामिक्स, कहानी की पुस्तकें रहेंगी। कक्ष की दीवारों पर बच्चों के मनोरंजन के लिए डारिमोन, छोटा भीम, मोगली समेत कई कार्टून बनाए जाएंगे। ऐसा होगा माहौल

- बच्चों के रहने के लिए बेड की व्यवस्था की जाएगी। जरूरत पड़ने पर उनके माता-पिता भी रह सकेंगे।

- खेलने के लिए खिलौने, टीवी और म्यूजिक सिस्टम रहेगा।

- जानकारी देने वाले हॉटलिंग्स लगाए जाएंगे। कुर्सी, मेज, वाटर कूलर और अलमारी रहेगी।

- कैदियों के संपर्क से दूर रखा जाएगा।

स्थानीय ग्रामीण सम्पत्तियों का मूल्यांकन करने के निर्देश



देहरादून, संवाददाता। मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में उनके सचिवालय सभागार में 15 वें वित्त आयोग के अनुश्रवण के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने नियोजन और पंचायती राज विभाग के साथ ही सम्बन्धित रेखीय विभाग को 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप अनुदान एवं अनिवार्य गतिविधियों के लिये जारी धनराशि के उपयोग की निगरानी तथा स्थानीय ग्रामीण सम्पत्तियों का मूल्यांकन करने के निर्देश दिये ताकि अनुदान की धनराशि का समय पर प्रभावी उपयोग तथा वित्तीय वर्ष में स्थानीय ग्रामीण निकायों द्वारा निधि का समुचित उपयोग किया जा

सके। उन्होंने स्थानीय स्तर पर पेयजल, स्वच्छता, सड़क, पथ प्रकाश, सामुदायिक केन्द्र, जल निकासी आदि जरूरतों के सुचारू क्रियान्वयन के लिये सम्बन्धित रेखीय विभागों को आपसी समन्वय बनाते हुए विकास कार्य करने के निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने आबद्ध अनुदान (टाइड फंड) का अनिवार्य रूप से 50 प्रतिशत टोस अपशिष्ट प्रबंधन में खर्च करने तथा अधिक जनसंख्या के घटते क्रम में कम से कम 2 प्रतिशत पंचायतों की संपत्ति का मूल्यांकन करने तथा धनराशि का बेहतर उपयोग करने हेतु निगरानी करने के निर्देश दिये। उन्होंने विकास कार्यों से सम्बन्धित जन शिकायतों पर गम्भीरता से संज्ञान लेने तथा सम्बन्धित

जोशीमठ आपदा: 34 लोगों के शव बरामद, 9 की हो चुकी शिनाख्त, छह उत्तराखंड के

कोटद्वार, संवाददाता। वन प्रभाग पौड़ी की पोखड़ा रेंज में आग बुझाते हुए चट्टान से गिरकर दो वन कर्मियों की मौत हो गई थी। इस घटना पर दुख जताते हुए वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि मृतक परिवारों को सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। आपदा प्रबंधन के तहत परिवारों को चार-चार लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।

पोखड़ा रेंज के अंतर्गत ल्वीठा के पास जंगल में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना पर आग बुझाने के लिए मौके पर करीब चार वन कर्मियों की टीम भेजी गई थी। इस दौरान वन दारोगा दिनेश लाल और वनरक्षक हरिमोहन दो अन्य साथियों के साथ

नीचे रास्ते में आग बुझाने गए थे। वापस आते हुए साथियों ने उनकी खोजबीन की तो वे चट्टान से नीचे गिरे हुए मिले। घटना में हरिमोहन की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि दिनेश लाल ने अस्पताल पहुंचते हुए दम तोड़ा। दोनों वन कर्मियों का कोटद्वार में पोस्टमॉर्टम के बाद मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। वहीं वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार की ओर से दोनों वन कर्मियों के परिवारों को हर संभव मदद की जाएगी। उन्हें आर्थिक सहायता के उपरांत नौकरी भी दी जाएगी। हरक सिंह रावत ने कहा कि आपदा प्रबंधन के तहत मृतक परिवारों को चार-चार लाख रुपए धनराशि दी जाएगी।

दर्जाधारी राज्यमंत्री ने आंगनबाड़ी वर्कर की सुनीं फरियाद

काशीपुर, संवाददाता। जसपुर में उत्तराखंड महिला आयोग की उपाध्यक्ष एवं दर्जा राज्यमंत्री सायरा बानो आंगनबाड़ी वर्कर की शिकायत पर जांच करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने समस्त आंगनबाड़ी वर्करों के साथ एक बैठक भी की। वहीं, बैठक में राज्यमंत्री सायरा बानो ने शिकायतकर्ता वर्कर की बात सुनीं, मीटिंग में उपजिलाधिकारी जसपुर भी मौजूद रहे। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो ने बताया कि एक कर्मचारी की ओर से शिकायत राज्य महिला आयोग में की गई थी, कि उसे पिछले 3 वर्षों से मानदेय नहीं मिला है। विभाग में लगातार उसका शोषण किया जा रहा है और उसके चार्ज का कार्य भी उसे नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं अब पीड़िता को उनके पद के अनुसार कार्य दे दिया गया है और उनका रुका हुआ मानदेय भी जल्द ही दिया जाएगा।

व्यवसायिक वाहनों में स्पीड गर्वनर लगाना सुनिश्चित करें

रुद्रपुर, संवाददाता। अपर जिलाधिकारी उत्तम सिंह चौहान की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में समस्त व्यवसायिक वाहनों में स्पीड गर्वनर लगाना सुनिश्चित करें, और जिस वाहन में स्पीड गर्वनर नहीं लगा हो उस पर आवश्यक रूप से वैधानिक कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु पुलिस विभाग परिवहन विभाग द्वारा निरन्तर प्रवर्तन कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि

भार वाहन में सवारी बैठाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग, ओवरलोडिंग, तेज रफतार, रेड लाईट जम्पिंग, नशे में वाहन चलाना आदि नियमों पर लापरवाही बरतने वाले लोगों पर वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि व्यवसायिक वाहनों एवं अन्य वाहनों में पंजीयनधफिटनेस के समय रिफ्लेक्टर टेप लगाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में पार्किंग स्थलों में खड़े वाहनों में भी रिफ्लेक्टर लगाएँ एवं लोगों को जागरूक भी करें। अपर जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि पैच

वर्कों के माध्यम से सड़कों के गड्ढों को भरने का कार्य शीघ्रता से किया जाए। उन्होंने एनएचएआई के पी डी योगेन्द्र शर्मा को निर्देश दिये जिला चिकित्सालय के सामने दुर्घटना को रोकने के हेतु तत्काल रम्बल स्ट्रैप बनवाना सुनिश्चित करें एवं सड़कों पर लाईटों की समुचित व्यवस्था हो। उन्होंने नगर निगम द्वारा आन्तरिक मार्गों में लाईटों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अपर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन करते समय चालक व स्वामी का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने कहा

संक्षिप्त समाचार....

आपसी विवाद में दंपति ने गटका जहर, पत्नी की मौत

काशीपुर, संवाददाता। आपसी विवाद में दंपति ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। आनन-फानन में दोनों को परिजनों ने मुरादाबाद रोड स्थित एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान पत्नी ने दम तोड़ दिया, जबकि पति की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम गडीनेगी के रहने वाले वीरेंद्र सिंह का विवाह 8 वर्ष उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के अफजलगढ़ के ग्राम राजनगर निवासी कोमल के साथ हुआ था। विजेंद्र सिंह दुर्गापुर में स्थित गुरुनानक सीड्स प्लांट में कार्य करता है। दंपति के परिजनों के मुताबिक, दोनों के बीच किसी बात को लेकर देर रात कहासुनी हो गई। जिसके बाद दोनों ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। कुछ ही देर में दोनों की हालत बिगड़ गई। दोनों को गंभीर हालत में काशीपुर में मुरादाबाद रोड स्थित एक निजी चिकित्सालय में भर्ती किया गया। जहां उपचार के दौरान आज सुबह कोमल ने दम तोड़ दिया। जबकि उसके पति वीरेंद्र की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है।

कुर्मी महासभा ने छात्र संघ के समर्थन में दिया ज्ञापन

रुद्रपुर, संवाददाता। कुर्मी महासभा के संस्थापक एवं केंद्रीय अध्यक्ष सौरभ गंगवार ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपकर छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव करने वाले अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। संस्थापक एवं केंद्रीय अध्यक्ष सौरभ गंगवार ने बताया कि वर्तमान में महाविद्यालय में चल रही विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया में महाविद्यालय में कार्यरत समाजशास्त्र के प्रोफेसर हेमलता सैनी एवं रविंद्र सैनी द्वारा प्रवेश चाहने वाले पिछड़ी जाति वर्ग के छात्र, छात्राओं के साथ भेदभाव कर पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को शासन द्वारा प्रदत्त आरक्षण के लाभ से वंचित कर रहे हैं एवं इस संबंध में संबंधित छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के उक्त प्रोफेसर से संपर्क करने पर प्रोफेसरों द्वारा अभिभावकों के साथ अभद्रता की जाती है जिससे छात्र छात्राओं के अभिभावकों में भी रोष व्याप्त है। संस्थापक एवं केंद्रीय अध्यक्ष सौरभ गंगवार ने मांगी है कि उन पर छात्रों के साथ भेदभाव करने वाले प्रोफेसर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें अगर उन प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो कुर्मी महासभा आंदोलन के बाध्य होगी।

90 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू

अल्मोड़ा, संवाददाता। क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी वाई0एस0 रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 30 गाईडलाइन्स के अन्तर्गत जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ हो चुके हैं। एनएसडीसी से नामित प्रशिक्षण प्रदाता जेआईटीएम स्किल्स प्रा0 लि0 नामित है। जिनके द्वारा मोबाइल फोन हार्डवेयर रिपेयर, टैक्निशियन एवं सुईंग मशीन आपरेटर में अल्पावधि अधिकतम 90 दिन का प्रशिक्षण प्रारम्भ हो चुका है। उन्होंने बताया कि पीएमकेवीआई की गाईडलाइन के अनुसार जिला कौशल समिति को प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु मोबाइल/लाइसेंस सम्बन्धित दायित्व के अनुपालन में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय द्वारा पर्याप्त कार्यवाही की गई है। जिसमें दैनिक समाचार पत्रों में प्रचार-प्रसार, सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत अर्हयुवाओं को डाटाबेस से बल्क एसएमएस के माध्यम से मोबाइल/लाइज किया गया।

नमामि गंगे परियोजना के तहत निर्माणाधीन घाटों का क्रिया निरीक्षण

उत्तरकाशी, संवाददाता। नमामि गंगे जलशक्ति मंत्रालय भारत सरकार के तहत उत्तराखंड की नमामि गंगे की राज्य परियोजना प्रबंधन ग्रुप के अधिकारियों ने उत्तरकाशी जिले में गंगा किनारे प्रस्तावित व निर्माणाधीन घाटों का निरीक्षण किया। गंगोरी में असी गंगा व गंगा नदी के संगम तट पर प्रस्तावित 5 करोड़ 35 लाख के घाट का निरीक्षण किया। गणेशपुर में शिवानंद आश्रम के समीप गंगा नदी पर प्रस्तावित 3 करोड़ 45 लाख रुपये के घाट का निरीक्षण उत्तरकाशी में इंद्रावती नदी व गंगा नदी के संगम पर प्रस्तावित इंद्रावती घाट 4 करोड़ 30 लाख रुपये धनपति नदी पर प्रस्तावित घाट 4 करोड़ 40 लाख के घाटों का मौके पर निरीक्षण किया। मनेरी सेवा आश्रम के समीप निर्माणाधीन 7 करोड़ 13 लाख के घाट का निरीक्षण किया।

कि सम्बन्धित अधिकारी ई-रिक्शा के रूटों को निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक रूट के अनुसार ई-रिक्शा पर निर्धारित रंग की पट्टी लगाना सुनिश्चित करें ताकि उनके पट्टी के रंग के आधार पर ई-रिक्शा के रूट की पहचान किया जा सके। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी के ई-रिक्शा चालक द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाए तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही अनिवार्य रूप से की जाए। अपर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जिन स्थानों पर अतिक्रमण पूर्व में हटाया जा चुका है वहां पुनः अतिक्रमण न हो। और भविष्य में अधिकारी ध्यान रखें की अतिक्रमण होने किसी भी दशा में होने न दिया जाए। उन्होंने तहसीलदार अमृता शर्मा को निर्देश दिये कि किसी भी विभाग को भूमि आवंटन करने से पूर्व आवंटन करने वाली भूमि की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। ताकि बाद में सम्बन्धित विभाग को किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने सीओ ट्रैफिक, एआटीओ, एसडीएम एवं पी डी एनएचएआई की टीम गठित कर एन एच मार्गों का निरीक्षण कर 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि किन स्थानों पर डिवाइडर खोले जाये अथवा नहीं।

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में ये भारतीय स्पिनर कर सकता है डेब्यू, अजिंक्य रहाणे ने दिए संकेत

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और इंग्लैंड के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार से शुरू हो रहा है। पहला मैच हारने के बाद सीरीज में पिछड़ने वाली टीम इंडिया हर हाल में यह मैच जीतना चाहेगी। टेस्ट चौपियनशिप फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत का यह मैच जीतना जरूरी है। उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मैच से पहले मीडिया से बात करते हुए इस बात के संकेत दिए हैं कि फिट होकर वापसी करने वाले स्पिनर अक्षर पटेल को टेब्यू का मौका मिल सकता है। मैच से एक दिन पहले रहाणे ने कहा, घ्यह पिच पूरी तरह से अलग होगी। मैं पक्का यकीन रखता हूँ कि यह पहले दिन से ही डर्न लेगी लेकिन जैसा की मैंने पहले टेस्ट की शुरुआत से पहले भी कहा था कि हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा की पहले सेशन में खेल कैसा होता है और इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। पहले टेस्ट मैच के दौरान जो कुछ भी हुआ उसे हमको

कप्तान जो रूट ने बताया, क्यों जोफ्रा आर्चर और जेम्स एंडरसन को किया बाहर

चेन्नई, एजेंसी। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने शुक्रवार को पुष्टि की कि जोफ्रा आर्चर और जेम्स एंडरसन की जोड़ी भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध होगी। आर्चर की दाहिनी कोहनी में एक इंजेक्शन लगा है, जिसके कारण वे दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हैं, जबकि एंडरसन को दूसरे टेस्ट के लिए आराम दिया गया है, ताकि उन्हें अंतिम दो टेस्ट के लिए उपलब्ध कराया जा सके। कप्तान रूट ने 12 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। शुक्रवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रूट ने कहा, जोफ्रा ने पहले मैच में अपने आंकड़े से बेहतर गेंदबाजी की। उन्होंने टेस्ट टीम में शानदार वापसी। बेशक, यह एक झटका है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि वह खुद को तीसरे गेम के लिए तैयार कर लेंगे। इसलिए वह अगले कुछ हफ्ते समझदारी से काम लेंगे और खुद को देखभाल करेंगे। पूरी तरह से फिट होने में उनको समय लगेगा और सीरीज के बाकी मैचों के लिए वे फिर उपलब्ध होंगे।

कोहली हमारे कप्तान हैं और रहेंगे, कुछ मसाला नहीं मिलेगा- विराट पर पूछे सवाल पर रहाणे ने कहा

नई दिल्ली, एजेंसी। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच चेन्नई में ही शनिवार से खेला जाएगा। इस टेस्ट मैच से पहले भारतीय टेस्ट टीम के उप-कप्तान अजिंक्य रहाणे ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सवालों के जवाब दिए। इसमें से एक सवाल ये पूछा गया कि, भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पहले टेस्ट मैच में मिली हार के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों की शारीरिक भाषा को लेकर कहा था कि वो सही नहीं था। इसका जवाब देते हुए अजिंक्य रहाणे ने कहा कि, ये हमेशा संभव नहीं होता कि आप हमेशा एक ही तरह की एनर्जी के साथ मैदान पर उतरें। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में कई बार भारतीय खिलाड़ियों



भूलना होगा और कल सभी को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।

हम सबको मिलकर एक टीम की तरह से खेलना होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रही टेस्ट सीरीज का पहला मैच भी चेन्नई के एमए चिदंबरम में ही खेला गया था। इस मैच में भारतीय टीम को 227 रन की बड़ी हार झेलनी पड़ी थी। इस हार के बाद पिच क्यूरेटर को बीसीसीआई ने हटा

दिया था और दूसरे टेस्ट मैच के लिए पिच को टीम मैनेजमेंट की देखरेख में तैयार कराया गया है। लगातार एक ही मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच में खेलने के सवाल पर रहाणे ने कहा, विकेट बिल्कुल से अलग होगा और हमें इसके मुताबिक ढलना होगा। हमने चेन्नई में काफी क्रिकेट खेला है। यह पहली बार है जब एक ही मैदान पर हम लगातार दो टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं।

करियर में जमाया सिर्फ 1 दोहरा शतक लेकिन रच दिया इतिहास

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रही चार मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार 13 फरवरी से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाना है। यह मैदान उस खास हस्ती की यादगार पारी से जुड़ा है जिसे असली जेंटलमैन क्रिकेटर कहा जाता है। 12 फरवरी 1949 को कर्नाटक जिसे कभी मैसूर के नाम से जाना जाता था में जन्मे गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ आज अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपने पहले ही मैच में शतकीय पारी खेलकर सुर्खियां बटोरने वाले विश्वनाथ ऐसे एक मात्र भारतीय हैं जिन्होंने डेब्यू फर्स्टक्लास मैच में दोहरा शतक जमाया हो। भारत की तरफ से 91 टेस्ट और 25 वनडे मैच खेलने वाले इस दिग्गज बल्लेबाज को कलाई का जादूगर माना जाता था। टेस्ट में उनके नाम 14 शतकीय पारी और 222 रन की सर्वश्रेष्ठ पारी के साथ कुल 6080 रन हैं। वनडे में उनका करियर कुछ खास नहीं रहा और 19 की औसत से उन्होंने महज 439 रन ही बनाए। विश्वनाथ ने अपने 91 टेस्ट मैच के करियर में महज एक दोहरा शतक बनाया था लेकिन यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में दोहरा शतक बनाने वाले वह पहले भारतीय बल्लेबाज बने थे। 1982 में इंग्लैंड के खिलाफ 374 गेंद पर 222 रन की पारी खेली थी। इस पारी में उन्होंने 39 चौके लगाए थे और स्ट्राइक रेट 59.36 का रहा था। यह मैच ड्रॉ रहा था। साल 1979-80 में भारत के दौरे पर आई इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाज बॉब टेलर मुंबई टेस्ट में अंपायर द्वारा आउट करार दिए गए थे। कपिल देव की गेंद पर गेंद बॉब के बल्ले के पास के गुजरी और अंपायर ने उनको कैच आउट करार दिया। विश्वनाथ ने इस फैसले के विरुद्ध जाकर खेल भावना का परिचय देते हुए बॉब के वापस बल्लेबाजी के लिए बुलाया।



की एनर्जी में कमी लगी और ऐसा विराट कोहली की वापसी की वजह से नहीं था। कई बार हमें भी मैदान पर एनर्जी की कमी लगती है। विराट कोहली हमारे कप्तान हैं और वहीं रहेंगे। आपको कुछ मसाला नहीं मिलेगा यहां। टीम इंडिया को पहले टेस्ट मैच में 227 रन से हार

मिली थी और इसके बाद भारतीय टीम के चयन को लेकर कप्तान विराट कोहली पर काफी निशाना साधा गया था। इस मैच में मिली हार के बाद कप्तान विराट ने कहा था कि, हमारी टीम के खिलाड़ियों का अप्रोच सही नहीं था और शारीरिक भाषा भी सही नहीं थी।

व्यापार

बिल्कुल नए अंदाज में हुआ जावा 2.1 का लॉन्च

हल्द्वानी। जावा 2.1 के आगमन की घोषणा के साथ ही, जावा फोर्टी-टू परिवार में तीन नए सदस्य शामिल हो गए। क्लासिक लेजेंड्स को इस बात की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि इसके मॉडल लाइन-अप में शामिल की गई नई बाइक्स कंपनी के सभी डीलरशिप में उपलब्ध होंगे। जावा 42 सही मायने में 'श्रेट्टो कूल' रिवॉल्यूशन को आगे ले जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2018 में इसके लॉन्च के साथ की गई थी और अब इसमें क्लासिक स्पोर्ट्स बाइक की विशेषताओं को भी शामिल किया गया है। दिल्ली में इस मोटरसाइकिल की एक्स-शोरूम कीमत 1,83,942 रुपये है। इस नई मोटरसाइकिल के आगमन के बारे में बताते हुए, आशीष सिंह जोशी, सीईओ क्लासिक लेजेंड्स ने कहा, "पिछले साल हमने बाइक्स के बीएस 6 वर्जन को लॉन्च किया। लेकिन हमारी कोशिश यहीं खत्म नहीं हुई और हमने खुद से ही मुकाबला करते हुए अपने मोटरसाइकिलों के प्रदर्शन और अनुभव को ओर



बेहतर बनाया है, जिसे हमने 2.1 का नाम दिया है। हमने एग्जॉस्ट नोट को और ज्यादा श्रोती तथा पहले की तुलना में अधिक आकर्षक बनाया है, साथ ही हमने सीट का आकार बढ़ाया है तथा लुक को और जोरदार बनाने के लिए हमने क्रॉस पोर्ट इंजन में थोड़े सुधार किए हैं। हमारे ग्राहकों ने शुरू से ही जावा 42 का उपयोग अपनी रचनात्मकता की अभिव्यक्ति के लिए एक कैनवस के रूप में किया है। इस बात से प्रेरणा लेते हुए, हमने स्टैंडर्ड फिटमेंट के रूप में शक्लासिक स्पोर्ट्स स्टाइप्स, अलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर्स, ट्रिप मीटर और एक्ससेसरीज के रूप में फ्लाइ-स्क्रीन और हेडलैंप ग्रिल के साथ तीन नए कलर स्कीम को शामिल किया है। जावा और फोर्टी-टू बाइक्स की पूरी रेंज में टेकोलॉजी से जुड़े सभी अपडेटेड उपलब्ध होंगे, साथ ही ग्राहकों के पास नए एक्ससेसरीज चुनने का विकल्प भी होगा।

हवाई यात्रा करना होगा और मंहगा, सरकार ने किराये में की 30% तक बढ़ोतरी

नई दिल्ली, एजेंसी। अगर आप भी फ्लाइट्स में सफर करते हैं और कहीं घुमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि अब हवाई टिकट बुक करने पर आपको तगड़ा झटका लग सकता है। जी हां, भारत में अब घरेलू हवाई यात्रा आपको महंगी पड़ने वाली है। जानकारी के मुताबिक, सरकार ने अब प्राइस बैंड को खत्म करने का फैसला किया है जिसके तहत अब घरेलू हवाई का किराया न्यूनतम 10 प्रतिशत और अधिकतम 30 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। बता दें कि यह नई सीमाएं 31 मार्च, 2021 तक या आने वाले अगले आदेश तक लागू रहेंगी। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस फैसले को असाधारण उपाय करार दिया है और कहा कि उड़ान सेवाएं कोविड-19 के स्तर पर जैसे ही पहुंच जाएंगी वैसे ही हवाई किरायों में प्राइस बैंड को खत्म कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि, कोरोना महामारी के कारण 21 मई को फिर से उड़ानें शुरू करने से पहले मंत्रालय ने हवाई उड़ान की अवधि के आधार पर सात बैंड के लिए फ्लाइट्स के किराये पर सीमाएं लगाई थीं। जानकारी के मुताबिक, कोरोना महामारी के कारण हवाई यात्रा 23 मार्च 2020 को पूरी तरह बंद कर दिया गया था और 25 मई को कोरोना के नए गाइडलाइंस के मद्देनजर इसे दोबारा बहाल किया गया। पुरी ने बयान में कहा कि, 'हमारा प्रयास हमेशा से यह रहा है कि वास्तविक एवं संभावित यातायात से थोड़ा अधिक खोला जाए। उन्होंने कहा कि, हमें उम्मीद है कि गर्मियों तक उड़ानें कोविड पूर्व के स्तर पर आ जाएंगी तो हमें प्राइस बैंड की जरूरत नहीं होगी।

राज्यसभा में बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यह बजट आत्मनिर्भर भारत के लिए है

नई दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि 2021-22 का बजट आत्मनिर्भर भारत के लिये है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हर वर्ग के लिये काम कर रही है कि और साठगांठ वाले पूंजीवाद का आरोप लगाना बेबुनियाद है। सीतारमण ने राज्यसभा में 2021-22 के बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही। पूंजीपतियों के बजट के विपक्ष के आरोप का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "सरकार हर वर्ग के लोगों के लिये काम कर रही है, चाहे वह गरीब हों या फिर उद्यमी। हम पर साठगांठ वाले पूंजीवाद का आरोप लगाना बेबुनियाद है। गांवों में सड़कों का निर्माण, सौभाग्य योजना के तहत हर गांव में बिजली, छोटे किसानों के खातों में पैसा डालने जैसी योजनाएं गरीबों के लिये हैं न कि पूंजीपतियों के लिये।" उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत के लिये है। सीतारमण ने कहा कि यह सरकार गरीबों के साथ विनिर्माण को बढ़ावा देने को लेकर उद्यमियों के लिये भी काम कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा, "बजट में तात्कालिक सहायता के साथ साधमध्यम और दीर्घअवधि में सतत आर्थिक वृद्धि बनाये रखने पर ध्यान दिया गया है।" पीएम सम्मान निधि के तहत राशि कम किये जाने के विपक्ष के आरोप में उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल की तरफ से छोटे एवं सीमांत किसानों की सूची नहीं देने से पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2021-22 के लिये आबंटन 10,000 करोड़ रुपये कम किया गया है।

